(b) Scrapping of the vehicles is done in accordance with the norms prescribed for the purpose. For the DTC buses, it is 3 years of service or performance of 5 lakh kms. The vehicle can also be scrapped if it was involved in major accidents where the cost of repair becomes prohibitive and when it is considered uneconomical to run it further. The decision to scrap a bus is taken by the DTC Board after considering the recommendations made by a team of Engineers constituted for the purpuse of scrapping.

Students' agitation and their demands

*176. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether there have been students' agitations including demonstrations, strikes, etc., in Bihar and other States durig the present year; and if so, their main demands and Government's reaction thereto;

(b) whether students of different universities in Bihar and other States are demanding among others, abolition of private tuition, guaranteed tutorial, timely academic session; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) to (c). There have been reports about students' agitations in different parts of the country during the current year either in support of their demands or in protest against actions taken by University authorities/local administration. In a majority of cases, the agitaitons start on purely local issues some of which may be academic in nature like abolition of private tuition, request for timely academic session etc.

Out of 112 Universities in India, 105 are functionig under the State legislation and maintained by the State Governmets. It is, therefore, for the concerned State Governments to take appropriate action in each case. Even in the case of seven Central Universities, it is primarily for the University authorities to look into various demands or otherwise to deal with the situations.

अहमदाबाद में सर्कुलर रेलवे

*177. श्री नरसिंह मकवाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद सिटी में सर्कुलर रेलवे आरम्भ करने के लिये उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को लागू करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) यह सर्कुलर रेलवे कब तक चालू हो जायेगी और इसकी लम्बाई कितने किलोमीटर है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से लिख कर अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ). अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण और अहमदाबाद नगर निगम अहमदाबाद क्षेत्र के लिए दैनिक यात्री रेल सेवा का तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिक सर्वेक्षण करने के बारे में विचार कर रहा था जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक हो गई है । राज्य सरकार के अनुरोध पर, रेल मंत्रालय ने निक्षेप कार्य के

रूप मे अहमदाबाद क्षेत्र के लिए महानगरीय दैनिक जाल-तंत्र का व्यावहारिकता अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) को प्राधिकृत किया है। द्रुत परिवहन लाइन की लम्बाई और उसे पूरा करने मे लगने वाले समय का तभी पता चलेगा जब महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) द्वारा प्रारम्भ किया जाने वाला व्यावहारिकता अध्ययन पूरा हो जायेगा।

2. तदनुसार, महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) ने अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण से अनुमानित रकम जमा करने के लिए कहा है ताकि वे सर्वेक्षण-कार्य प्रारम्भ कर सकें। अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण द्वारा अहमदाबाद क्षेत्र के लिए दैनिक सेवा की लाइन का तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के प्रस्तावो पर अपने स्वीकृति देते समय प्रस्तावित सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन तथा वित्त-पोषण के सम्बन्ध मे योजना आयोग और रेल प्राधिकारियो की वचनबद्धता जानना चाहते थे। महानगर परिवहन परियोजना बम्बई सगठन ने अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण को सूचित किया है कि योजना आयोग से ऐसी वचनबद्धता की आशा रखना असामयिक होगा क्योंकि दैनिक यात्री लाइन की आवश्यकता को तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण के माध्यम से सुस्थापित किया जाना होता है।

3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण ने जुलाई, 1981 में महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) को सूचित किया है कि यह प्रस्ताव उनके विचाराधीन है बशर्ते कि अहमदाबाद नगर निगम कुल लागत की 70 प्रतिशत लागत वहन करे क्योंकि 30 प्रतिशत राशि अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ही वहन की जायेगी बशर्ते कि राज्य सरकार इसकी स्वीकृति दे दे। यह मामला अभी भी अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

भटिण्डा-गंगानगर ब्राड गेज लाईन को सूरतगढ़ से जोड़ना

*178. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगानगर क्षेत्र की मंडियों का विकास करने की दृष्टि से भटिंडा-गंगानगर (बरास्ता अबोहर) ब्राड गेज लाईन को सूरतगढ जंक्शन ब्राड गेज लाइन से जोडने के बारे में कोई योजना विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाईन के द्वारा मडी पदमपुर सहित किन-किन मडियों को जोडा जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दुमालकोट के रास्ते अबोहर श्रीगंगानगर के साथ बडी लाइन द्वारा पहले से ही जोडा हुआ है। धन की अत्यधिक कमी के कारण पदमपुर के रास्ते श्रीगंगानगर से सूरतगढ तक नई लाईन का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं होगा।

फालोडी स्टेशन पर नमक के लदान के लिये माल डिब्बे

*179 **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे अधिकारियों द्वारा फालोडी स्टेशन